01 JULY 2024 M4U:Layout 1 30-Jun-24 11:24 PM Page 1

दैनिक

जनता की आवाज

मीडिया फॉर यू

प्रकाशन के 09 वर्ष

RNI: UPHIN/2015/65169

सोमवार 01 जुलाई 2024

वर्ष: 09, अंक: 158

पृष्ठ: 04 मूल्य: 02 रुपया

गाजियाबाद से प्रकाशित हापुड़ ❖ मेरठ ❖ शामली ❖ मुजफ्फरनगर ❖ बागपत ❖ सहारनपुर ❖ बिजनौर ❖ दिल्ली एनसीआर में प्रसारित

Email:- m4unews@gmail.com 8445657566

एक दरोगा व सिपाही को किया... 4

नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संभाला कार्यभार, मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात

लखनऊ। 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह यूपी के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उन्होंने शाम करीब चार बजे अपने कार्यालय में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने रविवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक बार और सेवा विस्तार मिल सकता है। कयास के उलट मनोज कुमार सिंह प्रदेश के मुख्य सचिव बने। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और दोनों रहेंगे।

मनोज कुमार सिंह 1987 बैच के अरुण सिंघल, इसी बैच की लीना नंदन और 1988 बैच के रजनीश दुबे को सुपरसीड करके मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अरुण सिंघल और लीना नंदन केंद्रीय नियुक्ति पर हैं, जबकि रजनीश दुबे राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं।

मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। यही वजह है कि पिछले काफी समय से कृषि उत्पादन आयुक्त और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इससे पहले मनोज कुमार सिंह ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और मुरादाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं। ग्राम विकास आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी

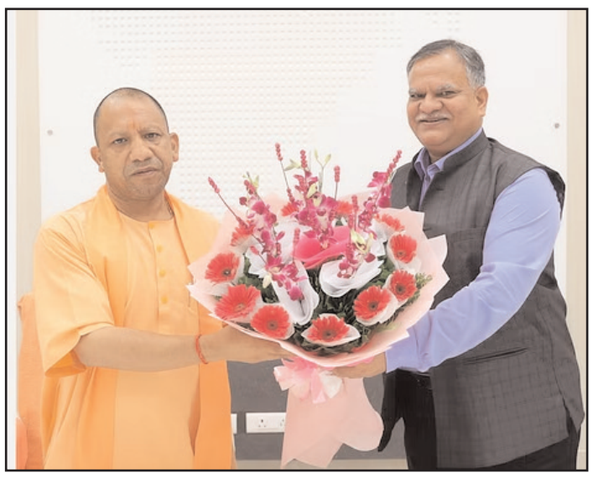

उन्होंने निभाई। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त भी रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई। वह भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे हैं।

दुर्गा शंकर को सेवा विस्तार न मिलने की स्थिति में यूपी कॉडर के 1987, 1988 और 1989 बैच के कई अफसरों की दावेदारी बढ़ गई थी। इसमें सबसे पहला नाम कृषि उत्पादन आयुक्त और आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह का ही था। वह 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और उनके पास मौजूदा समय में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी है। शासन की कई योजनाओं को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे में सेवा विस्तार न मिलने की स्थिति में मनोज कुमार सिंह इस पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। इसके अलावा भारत सरकार में सचिव पद पर तैनात अरुण सिंघल की वापसी भी मुख्य सचिव के तौर पर होने की चर्चा थी। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा एस चौहान रविवार को रिटायर हो जाएंगी। वह केंद्र में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में सचिव के पद पर तैनात हैं। शनिवार को डीओपीटी के सचिव का अतिरिक्त चार्ज 1984 बैच के अफसर व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को दे दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की पांच दिवसीय बांग्लादेश यात्रा शुरू

नयी दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने अपनी पांच दिवसीय बांग्लादेश यात्रा रविवार को शुरू की जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना तथा समुद्री क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशना है। त्रिपाठी की यह यात्रा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के एक सप्ताह से अधिक समय बाद हो रही है जिसके दौरान दोनों पक्षों ने समग्र रक्षा और रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया था। दो महीने पहले नौसेना की कमान संभालने के बाद एडमिरल त्रिपाठी की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है।

नौसेना प्रमुख का अपने बांग्लादेशी समकक्ष एडमिरल एम नजमुल हसन और थलसेना प्रमुख तथा वायुसेना प्रमुख सहित बांग्लादेश की सेना के अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा करने का कार्यक्रम है। एडमिरल त्रिपाठी चार जुलाई को चटगांव में बांग्लादेश नौसेना अकादमी (बीएनए) में पासिंग-आउट परेड का भी निरीक्षण करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, नौसेना प्रमुख ढाका स्थित बांग्लादेश के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में संबोधन करने सहित कुछ प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा, ह्यह्यइस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना तथा नौसैनिक सहयोग के नए रास्ते तलाशना है।

बिहार के बाद झारखंड में जमींदोज हुआ निमार्णाधीन पुल, भारी बारिश के कारण हुआ हादसा

झारखंड। बिहार के बाद अब झारखंड में एक निमार्णाधीन पुल गिर गया है। यह पुल गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में अरगा नदी पर बना रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार देर रात को हुई बारिश के बाद पुल का पिलर धंस गया था, जिसकी वजह से गर्डर टूटा और पुल जमींदोज हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा साढ़े पांच करोड़ की लागत से करवाया जा रहा था।

गिरिडीह से सड़क निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता विनय कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शनिवार रात भारी बारिश के कारण पुल का 'सिंगल-स्पैन' गर्डर गिर गया और एक पिलर झुक गया। ठेकेदार को उस हिस्से को दोबारा बनाने के लिए कहा गया है। स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार की शाम को मूसलाधार बारिश की वजह से अरगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। रात करीब आठ बजे एक पाया टेढ़ा हो गया, जिसके बाद तेज आवाज के साथ निमार्णाधीन पुल का गर्डर टूट कर नदी में गिर गया। स्थानीय ग्रामीणों ने एक अन्य पिलर के टेढ़े होने की भी जानकारी दी है। बता दें, ओम नमः शिवाय नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका मिला था। पहली बारिश भी नहीं झेल पाने की वजह से सरकार और कंपनी दोनों विवादों के घेरे में हैं।

जिला अधिकारी ने मोदी कॉलेज के चार छात्रों को टैबलेट और 21000 नगद एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

मीडिया फॉर यू

मोदीनगर। डॉ के एन मोदी डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदीनगर गाजियाबाद के इंटरमीडिएट के दो छात्र विवेक पुत्र श्री सुखराम ने 500 में से 477 अंक पाकर जनपद में तीसरा वह साहिल पुत्र श्री जोगिंद्र कुमार ने 500 में से 471 अंक पाकर जनपद में चौथा स्थान तथा हाई स्कूल के दो छात्रों आदित्य सिरोही पुत्र श्री सतेंद्र कुमार ने 600 में से 574 अंक पाकर जनपद में तीसरा तथा प्रथम पुत्र श्री मुकेश कुमार ने 500 में से 562 अंक पाकर जनपद में आठवां स्थान प्राप्त करने पर जनपद के जिलाधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह आई ए एस तथा मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव गोपाल आई ए एस तथा जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राजेश श्रीवास ने छात्रों को एक-एक टैबलेटड्ड21000 नगद तथा प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय ने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एस सी अग्रवाल जी को बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं दी साथी उन्होंने यह प्रेरणा भी दी की आने वाले वर्षों में विद्यालय के छात्र और अधिक ऊर्जा के साथ इसी प्रकार मेहनत करते रहें ताकि विद्यालय के छात्र प्रदेश स्तर पर अपना स्थान प्राप्त कर विद्यालय एवं अपने शहर के साथ-साथ माता-पिता जनपद का नाम भी

प्रदेश स्तर पर रोशन करने के लिए प्रेरित किया विद्यालय के अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर डीके मोदी जी उपाध्यक्ष कैप्टन राजीव सक्सेना जी व प्रबंधक श्री संदीप कुमार यादव जी ने छात्रों को बधाई दी और उन्होंने भी छात्रों को भविष्य में प्रदेश स्तर पर स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भी उन्हें बधाई दी उल्लेखनीय है कि इस विद्यालय के छात्र बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ खेल, एनसीसी स्काउट, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, विज्ञान प्रदर्शनी, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस और अन्य सभी गतिविधियों में जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रति भाग कर विद्यालय के साथ-साथ जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं इस वर्ष विद्यालय के 2 छात्रों का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मैं राष्ट्रीय स्तर के लिये हुआ है विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी श्री राजकुमार सिंह जी ने भी छात्रों को बधाई देकर उत्साह वर्धन किया।

कर्मचारियों के पास 31 अक्तूबर तक पेंशन विकल्प चुनने का मौका

लखनऊ एजेंसी। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्तूबर 2024 तक दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। इससे करीब 50 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में होंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया।

तमाम ऐसे शिक्षक और कार्मिक हैं, जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। ये कर्मी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है।

कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया।

शासनादेश के मुताबिक यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने की शर्तों को पूरा करता है तो प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बाद इस संबंध में एक आदेश नियुक्ति अधिकारी जारी करेंगे। आदेश

जारी होने के अगले महीने के वेतन से अभिदाता अंशदान और नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद हो जाएगी। जो कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुनेंगे, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। इन खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। इन खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा। 31 अक्तूबर तक विकल्प का प्रयोग न करने वाले कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आ जाएंगे। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संसद सत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को उठाए जाने के लिए शुक्रवार को संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। विजय बंधु ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, सांसद जगदंबिका पाल, कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रमोद तिवारी, उज्ज्वल रमण सिंह, राकेश राठौर, आप सांसद संजय सिंह आदि से मुलाकात की। इसके माध्यम से उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने व निजीकरण समाप्त करने का मुद्दा संसद में उठाने की मांग की।

बारिश की वजह से 11 लोगों की मौत, दिल्ली सरकार देगी 10 लाख मुआवजा

नई दिल्ली एजेंसी। दिल्ली सरकार ने रविवार को 28 जून को हुई भारी बारिश के बाद डूबकर मारे गए सभी लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें, शुक्रवार को दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश हुई थी, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी के निचले हिस्सों में जलभराव हो गया और 11 लोगों की जान भी चली गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

मंत्री आतिशी ने एसीएस राजस्व को निर्देश दिया कि वे क्षेत्रीय अस्पतालों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से जान गंवाने

वालों की पहचान करें और उन्हें जीएनसीटीडी की ओर से तत्काल मुआवजा प्रदान करें। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने लिखा, '28 जून को 24 घंटे में 228 मिमी की अत्यधिक बारिश के बाद कई मौतें हुई हैं। जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को ड्ड10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि यह मुआवजा पीड़ित परिवारों तक शीघ्र पहुंचे।' दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने रविवार को भारी बारिश से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा किया और जल निकासी प्रणालियों का निरीक्षण किया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को मानसून ने राष्ट्रीय राजधानी में दस्तक दी और इसकी पहली बारिश हुई। विभाग के अनुसार सफदरजंग में देर रात 2.30 बजे से सुबह 5.30 बजे के बीच तीन घंटे में 153.7 मिलीमीटर भारी बारिश दर्ज की गई।

नागपुर में नकली दवाइयों के गिरोह का भंडाफोड़ मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार

नागपुरः महाराष्ट्र के नागपुर जिले की पुलिस ने नकली दवाइयों के गिरोह का भंडाफोड़ किए जाने की घटना के सिलसिले में उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। नागपुर पुलिस ने मार्च 2023 में इस गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उन्होंने बताया कि नागपुर जिले के कलमेश्वर पुलिस थाने की एक टीम ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रमन विजयकुमार तनेजा को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मार्च 2023 में, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने नागपुर से लगभग 40

किलोमीटर दूर कलमेश्वर तहसील में एक सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से ह्यसिप्रोफ्लॉक्सासिनह्ल गोलियों के नमूने लिए थे और उन्हें परीक्षण के लिए मुंबई की एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजा था। पुलिस ने बताया कि दिसंबर 2023 में आई जांच रिपोर्ट से पता चला कि इन गोलियों का कोई औषधीय महत्व नहीं था, क्योंकि इनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन नामक दवा का कोई अंश नहीं था। इस दवा को कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन गोलियों की नागपुर स्थित इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के माध्यम से आपूर्ति की गई थीं, इसलिए एफडीए अधिकारियों ने इस वर्ष की शुरूआत में अस्पताल के स्टोर पर छापा मारा और उसी ब्रांड की 21,600 गोलियां जब्त कीं। पुलिस ने कहा कि गोलियों की पट्टियों से पता चलता है कि इनका निर्माण गुजरात स्थित एक कंपनी द्वारा किया गया था, जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। पुलिस ने शुरू में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया था - मुख्य आरोपी विजय शैलेन्द्र चौधरी, लातूर के हेमंत धोंडीबा मुले और भिवंडी के मिहिर त्रिवेदी। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान तनेजा का नाम सामने आया और हाल ही में चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया।

01 JULY 2024 M4U:Layout 1 30-Jun-24 11:24 PM Page 2

सम्पादकीय

सुविधाभोगी से संकट

प्रतिष्ठित लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की वह हालिया रिपोर्ट आईना दिखाने वाली है जिसमें पचास फीसदी भारतीयों के शारीरिक श्रम न करने का उल्लेख है। यहां शारीरिक श्रम से अभिप्राय सप्ताह में मध्यम गति की ढाई घंटे की शारीरिक गतिविधि या सवा घंटे की तीव्र गति वाली शारीरिक सक्रियता से है। शारीरिक सक्रियता को पैदल चलने, व्यायाम, सैर, योग, दौड़, जिम या तैराकी आदि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जहां पचास फीसदी वयस्क भारतीय शारीरिक श्रम से दूर हैं तो महिलाओं की स्थिति ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। उनकी निष्क्रियता का प्रतिशत 57 है। वैसे अकेले पुरुषों की निष्क्रियता का प्रतिशत 42 है। विडंबना यह है कि जैसे-जैसे समाज में शहरीकरण के चलते उपभोक्तावाद का विस्तार हुआ है, हमारी शारीरिक निष्क्रियता में इजाफा हुआ है। हम आरामदायक जीवन-शैली के आदी होते गये हैं। आशंका है कि वर्ष 2000 में भारतीयों में जो शारीरिक निष्क्रियता 22 फीसदी थी, वह वर्ष 2030 तक बढ़कर साठ फीसदी तक हो सकती है। यानी देश की साठ फीसदी आबादी गैर-संचारी रोगों मसलन डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे के दायरे में आ जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि भारतीयों में अनुवांशिक रूप से मधुमेह व हृदय रोग होने की आशंका अन्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जिसका निष्कर्ष है कि शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहने से हम इन बीमारियों को और जल्द आमंत्रित कर रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि जहां दुनिया में औसत शारीरिक निष्क्रियता पांच फीसदी बढ़कर 31 फीसदी हुई है, वहीं भारत में बढ़कर पचास फीसदी हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित शोधकताओं का मानना है कि भारत एशिया प्रशांत में उच्च आय वर्ग वाले देशों में निष्क्रियता के क्रम में दूसरे स्थान पर है। जहां तक महिलाओं की शारीरिक निष्क्रियता का प्रतिशत पुरुषों से अधिक यानी 57 फीसदी होने का प्रश्न है, तो उसके मूल में भारतीय पारिवारिक संरचना व सांस्कृतिक कारण भी हैं। घर-परिवार संभालने वाली महिलाओं में धारणा है कि घर का काम-काज ही शारीरिक सक्रियता का मापदंड है। जबकि यह समस्या की व्यावहारिक व्याख्या नहीं है। निस्संदेह, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। यह जानते हुए भी कि भारत लगातार मधुमेह और हृदय रोगों की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। दरअसल, आजादी के बाद देश में आर्थिक विकास को गति मिली है। भले ही हम अपेक्षित लक्ष्य हासिल न कर पाए हों, औसत भारतीय के जीवन स्तर में सुधार जरूर आया है। आर्थिक समृद्धि ने हमें सुविधाभोगी बनाया है। इस संकट की वजह शहरीकरण और जीवन के लिये जरूरी सुविधाओं का घर के आस-पास उपलब्ध हो जाना भी है। पहले देश की साठ फीसदी से अधिक आबादी कृषि व उससे जुड़े कार्यों में सक्रिय थी। मेहनतकश किसान को कोई शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं थी । लेकिन धीरे-धीरे कृषि में भी आधुनिक यंत्रों व तकनीकों ने शारीरिक श्रम की महत्ता को कम किया है। किसान संस्कृति से बड़ी संख्या में निकले लोगों ने शहरों को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन वे शारीरिक सक्रियता को बरकरार नहीं रख पाये। नौ से पांच की ड्यूटी करने वाले भी दफ्तर व घर के होकर रह गये। कहीं न कहीं सुविधाओं के विस्तार ने भी हमें आलसी बनाया। कुछ दूर पर सब्जी-फल लेने जाने पर भी हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शहरों में स्वास्थ्य चेतना का विकास नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद शहरों के पार्कों में सुबह गिने-चुने लोग ही नजर आते हैं। विडंबना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार और उसके बाद सोशल मीडिया की जकड़ में आने के बाद लोग देर रात सोने व देर से उठने के फेर में फंस गये हैं। सुबह के समय, जब लोगों को व्यायाम, सैर, योग व दौड़ लगानी चाहिए, वे सो रहे होते हैं। शरीर की प्राकृतिक घड़ी का चक्र बिगड़ने से दिन भर आलस्य बना रहता है। आज लोग कुछ न करने के बावजूद बहुत व्यस्त रहते हैं। लोग यदि अपने लिये रोज आधा घंटा भी निकाल सकें तो स्वस्थ रहने का मंत्र हासिल कर सकते हैं। यह हमारी आदत का हिस्सा बन जाना चाहिए।

अब भारत को विभिन्न क्षेत्रों में अपने सूचकांक तैयार करना चाहिए

प्रहलाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल ही के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवत जान बूझकर गलत दशार्या गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजेर देश को बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रा स्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है, अर्थात इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाकर पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है।

इसी प्रकार, भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, इस भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव क्यों कराए गए हैं, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, आदि। परंतु, भारतीय मतदाताओं ने इन लोक सभा चुनावों में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। न ही, ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और न ही गर्मी का प्रभाव चुनावों पर पड़ा। हालांकि सत्ताधारी दल को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ कम स्थान जरूर प्राप्त हुए हैं परंतु देश में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सामान्यतः शांति के साथ सम्पन्न हो गए। साथ ही, विपक्षी दलों को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक स्थान मिले हैं और उन्होंने भी चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है। चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वें स्थान पर बताई गई है। जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है, परंतु पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को ही जैसे खतरे में बताया जा रहा है और एक तरह से भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल पश्चिमी देशों में कुछ शक्तियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकतें विभिन्न सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़तीं हैं।

कुछ समय पूर्व एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में यह बताया गया था कि भारत की तुलना में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, एथीयोपिया, नेपाल, भूटान आदि देशों में भुखमरी की स्थिति बेहतर है। अर्थात, सर्वे में शामिल किए गए 121 देशों की सूची में श्रीलंका का स्थान 64वां, म्यांमार का 71वां, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां, एथीयोपिया का 104वां एवं भारत का 107वां स्थान बताया गया था। जबकि पूरा विश्व जानता है कि व श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है जिसके चलते इन देशों के नागरिकों के लिए दो जून की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि, भारत कई देशों को आज खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिर किस प्रकार उक्त सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि भारत की आर्थिक तरक्की को विश्व के कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारत के बारे में इस प्रकार के सूचकांक जारी कर भारत की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

युद्ध की विभीषिका झेल रहे एथीयोपिया में नागरिक अपनी भूख मिटाने के लिए घास जैसे भारी पदार्थों को खाकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जीवन यापन करने वाले नागरिकों को भुखमरी के मामले में भारत के नागरिकों से बेहतर स्थिति में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन लोगों को खाने पीने सम्बंधी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। फिर भी भारत के नागरिकों को भुखमरी सूचकांक में इथीयोपिया के नागरिकों की तुलना में इतना नीचे बताया गया है। अब कौन इस प्रकार के सूचकांकों पर विश्वास करेगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांक को आंकने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से केवल 3000 नागरिकों को ही इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वे का सैम्पल बनाते समय भारत जैसे विशाल देश के लिए अपर्याप्त संख्या का उपयोग किया गया है।

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग पर कार्य कर रही संस्था स्टैंडर्ड एंड पूअर ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था का आंकलन करते हुए भारत के सम्बंध में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक किया है एवं कहा है कि वह भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के उद्देश्य से भारत के आर्थिक विकास सम्बंधी विभिन्न पैमानों का, आधारभूत ढांचे को विकसित करने एवं भारत के राजकोषीय घाटे को कम करने से सम्बंधित आंकड़ों एवं प्रयासों का गम्भीरता से लगातार अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहा है। आगे आने वाले दो वर्षों के दौरान यदि उक्त तीनों क्षेत्रों में लगातार सुधार दिखाई देता है तो भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग इइइ- है, जो निवेश के लिए सबसे कम रेटिंग की श्रेणी में गिनी जाती है।

किसी भी देश की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को यदि अपग्रेड किया जाता है तो इससे उस देश में विदेशी निवेश बढ़ने लगते हैं क्योंकि निवेशकों का इन देशों में पूंजी निवेश तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। साथ ही, अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त देशों की कम्पनियों को अन्य देशों में पूंजी उगाहना न केवल आसान होता है बल्कि इस प्रकार लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की राशि भी कम देनी होती है। किसी भी देश की जितनी अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग होती है उस देश की कम्पनियों को कम से कम ब्याज दरों पर ऋण उगाहने में आसानी होती है। परंतु, भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए स्टैंडर्ड एंड पूअर को दो वर्षों का समय क्यों चाहिए? जब इन समस्त क्षेत्रों में लगातार सुधार होते साफ दिख रहा है।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई विदेशी संस्थान (विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आदि) आगे आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर बहुत उत्साहित हैं एवं आर्थिक प्रगति के साथ साथ राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करते रहते हैं। फिर भी, स्टैंडर्ड एंड पूअर को भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के लिय दो वर्षों का अतिरिक्त समय चाहिए।

वैश्विक पटल पर पश्चिमी देशों के विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के चलते, अब समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानों पर अपनी रेटिंग तय करने के लिए अपने सूचकांक विकसित करने पर विचार करे क्योंकि वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों द्वारा जितने भी सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं उसमें भारत के संदर्भ में वस्तुस्थिति का सही वर्णन नहीं किया जा रहा है।

- सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर - 474 009

राजेंद्र शर्मा के तीन लघु व्यंग्य

1. पर इस्तीफा कभी नहीं

यह तो विरोधियों की घनघोर टाइप की ज्यादती है। पहले इसकी रट लगा रखी थी कि नीट परीक्षा में गड़बड़झघोटाले के लिए नैतिक जिम्मेदारी लो। शिक्षा मंत्री ले एनटीए के निदेशक लेड्डू कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लो। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक जिम्मेदारी मान ली है तो भाई लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी और लगे मंत्री जी का इस्तीफा मांगने। जिम्मेदारी लेने की बात से सीधे इस्तीफा देने की मांग पर आ गए ; ऐसी धोखाधड़ी इस अपोजीशन की!

वह तो अच्छा हुआ कि मोदी जी ने अपने राज के शुरू में ही साफ कर दिया था कि कुछ भी हो जाए उनकी सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होगा। माने छुट्टी भी नई भर्ती भीड्डू सब कुछ होगा तो सही ; पर वही होगा, जो मोदी रचि राखा होगा। पर दूसरों के कहने से ही नई भर्ती इस्तीफा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इतना साफझसाफ कह देने के बाद भी मोदी जी कोई इस्तीफों की मांग से साफ बच गए हों। गुजरे दस साल में इस्तीफे की मांग का शोर उठा बारझबार उठा। पर इस्तीफा मांगने वाले जानते थे कि कुछ भी हो इस्तीफा नहीं मिलेगा। पब्लिक सब देखझ समझ रही थी कि कोई कुछ भी कर ले इस्तीफा नहीं होगा। सो इस्तीफा नहीं हुआ। और जब बाकी किसी का वैसा वाला इस्तीफा भी नहीं हुआ कि पब्लिक मांगे और नाझना करतेझकरते मंत्री आखिर में इस्तीफा दे डालेड्डू फिर किसी के मोदी जी का इस्तीफा मांगने का तो सवाल ही कहां उठना था। छप्पन इंच की छाती इंतजार ही करती रह गई पर उसे इस्तीफे की मांग को खारिज करने का मौका ही नहीं मिला।

सब अच्छाझभला चल रहा थाड्डू न कोई इस्तीफाड्डू न इस्तीफे की मांग का ज्यादा कोई शोर। पर तभी पब्लिक पगला गई। चार सौ पार वालों को तीन सौ से भी नीचे खिसका दिया। मोदी जी के सिंहासन की टांगें तोड़करड्डू नीतीश और नायडू की बैसाखियां फिट कर दीं। ऊपर से पहले दिन से इस्तीफे की मांग पर मांग। नीट और नेट के लिए प्रधानजी का इस्तीफा ; कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के लिए वैष्णव जी का इस्तीफा ; जम्मू कमीर में आतंकवादी वारदातों के लिए शाह साहब का इस्तीफा। यूं ही चला तो इस बार डिमांड कहीं मोदी जी के इस्तीफे तक न पहुंच जाए। सो और जोर से बोलोइस्तीफा कभी नहीं!

2. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी!

आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान जी को सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली फीलिंग आ रही होगी? जिस दिन मोदी की तीसरी पारी वाला नतीजा आया, उसी रोज नीट-यूजी का नतीजा निकाला। फिर भी नीट में घोटाले का शोर मच गया। ईवीएम तो छूट गयी, पर एनटीए की गर्दन फंस गयी। गर्दन भी ऐसी फंसी, ऐसी फंसी कि मंत्री जी जितने कहें कि सब चंगा सी, लोग उतना ही शोर मचाकर फंदा कसते जाएं कि सब घपला सी। हार के मंत्री जी बोले थोड़ा-बहुत घपला सी, पर बाकी सब चंगा सी, तो इसका शोर और तेज हो गया कि सब घपला ही सी। मंत्री जी ने कहा मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, तो लोगों ने और शोर मचा दिया कि लेने का मोह छोड़कर, आप तो बस दो -- इस्तीफा। तब तक उसी एनटीए की यूजीसी-नेट की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गयी। फिर उसी की सीआइएसआर वाली परीक्षा स्थगित हो गयी। फिर नीट-पीजी की परीक्षा। यानी ओले ही ओले और वह भी सिर मुंडाते ही।

पर सिर मुंडाते ही वाली फीलिंग हर्गिज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बेरोजगारी का इस बार के चुनाव में इतना हल्ला था, बल्कि जिसके चक्कर में ही चार सौ पार के एलान करने वाले मोदी जी को तीन सौ तक पहुंचना नसीब नहीं हुआ, मोदी 3.0 की तरफ से प्रधान जी ने तो उसका पक्का समाधान ही शुरू कर दिया है। पहले सौ दिन का रोडमैप! वैसे रोडमैप सिंपल है। ओन्ली परीक्षा पर चर्चा, नो पर्चा! अव्वल तो परीक्षा ही नहीं और परीक्षा हो भी जाए, तो पर्चा लीक यानी सिर्फ परीक्षा, नो नतीजा। प्रवेश परीक्षा का नतीजा नहीं, तो एडमीशन नहीं। एडमीशन नहीं, तो डिग्री-विग्री भी नहीं। न डिग्री, न डिग्रीधारी, तो रोजगार की मांग भी नहीं। बेरोजगारी का जड़ से और शर्तिया इलाज, ना रहे बांस, ना रहे बांसुरी वाला! शिक्षा वाले भी जड़ से इलाज नहीं बताएंगे, तो और कौन बताएगा!

मोदी 3.0 में जड़ से इलाज, सिर्फ इस-उस प्रवेश परीक्षा तक ही नहीं रहेगा। एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तकों में जड़ से इलाज पहले ही शुरू भी कर दिया है। कौन इंतजार करता है, चुनाव-वुनाव के नतीजे आने तक! ग्यारहवीं, बारहवीं की इतिहास की किताबों में अब सिर्फ राम मंदिर आंदोलन है, बाबरी मस्जिद सिरे से गायब है। इतने सिरे से कि उससे भव्य मंदिर के लिए जगह खाली कराए जाने तक का जिक्र नहीं है। असल में तो बाबरी मस्जिद के कभी रहे होने का ही जिक्र नहीं है। और बात भी सही है। मस्जिद तो खैर नहीं ही रही, पर उसके नाम के रूप में झगड़े की जड़ भी क्यों रहे? सो मस्जिद का नाम ही मिटा दिया। न रहेगी झगड़े की जड़ और न रहेगा झगड़ा। जब मस्जिद ही नहीं थी, तो उसका ध्वंस कैसा और मस्जिद का ध्वंस ही नहीं, तो उसके बाद का खून-खराबा कैसा? इसीलिए, 2002 का गुजरात का खून-खराबा भी मिटा दिया। अव्वल तो मोदी जी के सीएम रहते हुए कुछ खास हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कुछ हुआ भी, तो भी बुरा ही हुआ और जो बुरा हुआ, उसे याद करने का क्या फायदा? वह दिन दूर नहीं, जब किताबों से अंगरेजी राज भी मिट जाएगा। बस गांधी जी यहां भी दिक्कत खड़ी करने से बाज नहीं आएंगे। गोलियां दगना तो किताबों से मिटा भी देंगे, पर उस चक्कर में गोडसे का नाम भी तो मिट जाएगा। इतनी आसान भी नहीं है डगर, ना रहेगा बांस वाले पक्के इलाज की!

अब प्लीज ये बचकाना सवाल मत पूछने लग जाना कि जब बांस, बांसुरी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो अपने मोदी जी चैन की बांसुरी कैसे बजाएंगे? ये किसने कहा कि बांसुरी बांस से ही बन सकती है। मोदी जी स्पेशल बांसुरी बजाएंगे, अडानी जी की गिफ्ट की हुई, सोने की बांसुरी! शौक बड़ी चीज है!

3. ये दुश्मनी वो नहीं छोड़ेंगे!

भई दुश्मनी हो तो मोदी जी जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। पट्ठे केजरीवाल से दुश्मनी ठान ली, तो ठान ली। अब लाख चुन ले, दिल्ली की पब्लिक सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए। हजार बार अड़ जाए, अगला जान छूट जाए, पर कुर्सी नहीं छोड़ूं की जिद पर ; मोदी जी ने तिहाड़ की हवा खिलाने की ठान ली, तो तिहाड़ की हवा खिलाकर ही माने। सॉरी! हवा खिलाकर भी माने कहां हैं। अब भी तिहाड़ की हवा खिलाइंग एंड खिलाइंग एंड खिलाइंग!

विरोधियों ने क्या सोचा था? चुनाव में मोदी जी की बासठ-तिरेसठ सीटें कम हो गयी हैं, अपने बूते बहुमत से गैर-बहुमत में आ गए हैं, यूपी तक में अर्श से फर्श पर आ गए हैं, नायडू-नितीश की बैसाखियों के सहारे ही पीएम की गद्दी पर चढ़ पा रहे हैं, तो क्या मोदी जी अपनी दुश्मनी छोड़ देंगे? नायडू-नीतीश के सहारे हैं, तो क्या मोदी जी भागवत की बात मानकर, विरोधियों को दुश्मन तो छोड़ ही दो, विरोधी भी नहीं, सिर्फ प्रतिपक्षी मानने लग जाएंगे ; दुश्मनी भूलकर गले लगाने लग जाएंगे! कभी नहीं। अपना बस चलते तो केजरीवाल को जेल से बाहर आने नहीं देंगे। कर ले बंदा बाहर आने की कितनी भी कोशिशें! देखा नहीं कैसे निचली अदालत ने अगले को जमानत दे दी, तो मोदी जी की ईडी नंगे पांव हाई कोर्ट में पहुंच गयी, जमानत रोकी जाए, वर्ना बड़ा गजब हो जाएगा; भारतवर्ष खतरे में आ जाएगा। हाई कोर्ट ने फौरन तो राष्ट्र को बचा दिया, पर सुप्रीम कोर्ट के दखल देकर जमानत बहाल करने का खतरा तो राष्ट्र पर अब भी मंडरा रहा था। सो रिले रेस में शाह जी ने सीबीआइ को आगे कर दिया और सीबीआइ ने जेल से ही गिरफ्तारी कर के दूसरा ही राउंड शुरू कर दिया। अब ईडी के केस वाली जमानत किस काम की ; बंदा तो जेल में ही रहेगा। और अगर सीबीआइ वाले मामले में भी किसी तरह से जमानत मिल गयी तो? तो क्या, मोदी जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अदालत देख ले जमानत देकर। जरूरत पड़ी, तो अरविंद नाम वालों के लिए विशेष अध्यादेश ले आएंगे, पर जेल के फाटक से बाहर अगले के कदम नहीं पडड्डे दिए जाएंगे। इमर्जेंसी का सबक -- जब बिना इमर्जेंसी के ही विरोधी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले रखा जा सकता हो, तो मोदी जी इमर्जेंसी क्यों लगाएं!

(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

01 JULY 2024 M4U:Layout 1 30-Jun-24 11:24 PM Page 3

संक्षिप्त समाचार

भारतीय टीम द्वारा टी20 विश्व कप जीतने पर ककरौली मे मिठाई का वितरण कर मनायी गई खुशी

मीडिया फॉर यू, मीरापुर (मुजफ़्फ़रनगर)। काजी शाहिद अहमद

विधानसभा क्षेत्र के गांव में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन कर विश्व कप जीतने जीत पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मिठाई का वितरण कर खुशी मनाई। शनिवार को मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव ककरौली में भारतीय टीम की जीत पर खुशी मनाई गई। टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर विश्व कप पर कब्जा किया। इसी खुशी में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव एडवोकेट इमरान खान ककरौली के नेतृत्व में कार्यकताओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मुंह मीठा कराया। तथा ककरौली बाजार एवं मदरसे के पास मिठाई का वितरण कर ग्रामीणों के साथ खुशी साझा की। इस अवसर पर इमरान खान ने कहा की भारत ने विश्व में एक बार फिर से साबित कर दिया की भारत की किक्रेट टीम विश्व में नम्बर एक पर है। इस दौरान मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड के मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष तनवीर आलम, मौ० सलमान, मुस्तकीम अंसारी ढासरी, अब्दुल सलाम सलमानी, अली हसनैन, डा० अकरम, जावेद अंसारी नकीब कुरैशी, कलीम, मोनिश आदि मौजूद रहे ।

भाजपा नेता प्रमोद त्यागी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी

मीडिया फॉर यू, जितेंद्र शर्मा

जनपद मथुराः भाजपा नेता प्रमोद त्यागी ने 18वीं लोकसभा में पुनः लोक सभा स्पीकर चुने जाने पर उनके दिल्ली आवास पर पहुंचकर मुलाकात की भाजपा नेता श्री त्यागी ने ओम बिरला जी को पुष्प गुछ देकर हार्दिक बधाई दी व उसके उज्वल भविष्य की कामना की

पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए: प्रिंस कंसल

>> देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र

मीडिया फॉर यू

मोदीनगर। डॉ सपना मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रिंस कंसल ने एक मुलाकात में बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अन्याय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ होता है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो की अलग-थलग रहता है जिससे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी 600 किलोमीटर है और प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा पड़ती है इतनी दूरी में तो एक देश से दूसरे देश भी जाया जा सकता है इस दूरी के कारण ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे महंगा न्याय मिल पाता है ! प्रिंस कंसल ने बताया कि छः राज्यों (हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर) की राजधानी हमारी अपनी राजधानी लखनऊ से भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नजदीक हैं जिस कारण हमें अपने ही राज्य में अलग थलग होने का अहसास होता है है,यहाँ से हमारी राजधानी की दूरी 600 किलोमीटर है जो की पश्चिम उप्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है इसके अलावा सभी आयोग, मुख्यालय लखनऊ या इलाहबाद में स्थित हैं जिस कारण ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ भी यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वे लखनऊ तक आना-जाना वहन नहीं कर सकते हैं ! हमारे क्षेत्र से अधिकतर लोगों ने तो जीवन में कभी अपनी राजधानी के दर्शन भी नहीं किये होंगे !

प्रिंस कंसल ने बताया कि सांस्कृतिक रूप से भी पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिन्नता हैं ! महाभारत काल से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतिहास व संस्कृति पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत अलग रही है हम सांस्कृतिक रूप से हरियाणा दिल्ली व राजस्थान के बेहद करीब हैं जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति,भोजपुरी है !इसके अलावा हमारी भाषाशैली खड़ी बोली की है जबकि बाकि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी , बुन्देली आदि भाषा बोली जाती है इस भिन्नता की वजह से प्रदेश का सामाजिक व सांस्कृतिक विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ तक कि राज्य के जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं शिक्षा-रोजगार : हमारे यहाँ कोई ठक्ळ, क्क्ळ,अक्क्टर नहीं जो भी हैं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही हैं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 22 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिनमे से पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए मात्र 5 ही हैं इसके अलावा सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी भी 5 में से सिर्फ 1 ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में है साथ ही मैडिकल संस्थान एंव कॉलेजों में भी प्रदेश के 28 मेडिकल संस्थानों में से सिर्फ 5 ही पश्चिम में हैं आज भी पश्चिम क्षेत्र में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ की स्थिति दयनीय है यहाँ

बच्चों को सस्ती व गुणवत्तायुक्त शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है जिस कारण उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, इसके अलावा राज्य की सरकारी नौकरियों में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश न्यूनतम ही है ! राज्य में ढउर, ढढर और अन्य सरकारी नौकरियों में भी पश्चिम क्षेत्र की संख्या सबसे कम हैं (जनसँख्या अनुपात में) प्रिंस कंसल ने बताया कि खेलकूद के क्षेत्र में तो स्तिथि इतनी बदतर है कि पश्चिम में एक भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी आफ इंडिया (रअक) संस्थान नहीं है इसके अलावा राज्य सरकार के भी तीन खेल संस्थानो में से एक भी पश्चिम में नहीं है !

पूरे उत्तर प्रदेश में 73 राजकीय खेल स्टेडियम हैं जिनमें से सिर्फ दस ही पश्चिम में हैं और उनकी भी हालत बहुत खराब है इसी कारण कॉमनवेल्थ अथवा ओलंपिक खेलों में में यूपी के खिलाड़ियों का प्रदर्शन दयनीय रहता है !

कानून व्यवस्था के संदर्भ में प्रिंस कंसल ने बताया कि खराब कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सारे देश में बदनाम है इसका उपचार छोटे राज्य बनाकर किया जा सकता है (उदाहरण के लिए है की अगर एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और अन्य में 60 विद्यार्थी हैं तो पहली कक्षा में ही बेहतर पढ़ाई होगी) यही बात कानून व्यवस्था में भी लागू होती है,इतना बड़ा राज्य होने के कारण एक उन्न्ढ्ढ के लिए सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखना असंभव है अलग छोटा राज्य होगा तो कानून व्यवस्था में भी बहुत सुधार होगा

कृषि मामलों के विषय पर चर्चा करते हुए प्रिंस कंसल ने बताया कि पश्चिम के किसान खासतौर पर गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है,यहाँ के किसान की आय हरियाणा-पंजाब के किसान की आय से आधी रह गयी है जो की किसी समय पर इन राज्यों से अधिक हुआ करती थी ! गंगा यमुना की हमारी ये भूमि देश ही नहीं सारे विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है लेकिन फिर भी यहाँ का किसान अपने आप को बेबस और लाचार समझता है, गन्ना बेल्ट पश्चिम में है और गन्ना आयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में है !

उद्योग व्यापार के विषय में चर्चा करने पर प्रिंस कंसल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के राजस्व में 72% भागीदारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही है लेकिन फिर भी यहाँ के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितने का हक बनता है बेहतर बसअड्डे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, नए कॉलेज-यूनिवर्सिटी,इंडस्ट्रियल सेक्टर निर्माण से लेकर हर सरकारी योजना का अधिकतम लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही मिलता है और प्रदेश में सबसे ज्यादा आर्थिक भागीदारी देने के बावजूद भी यहाँ का रें वर्ग अपने पडोसी राज्यों से बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है` प्रिंस कंसल ने कहा कि बेहतर विकास के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना आवश्यक है विचारणीय है कि अलग राज्य बनने के बाद भी पश्चिम क्षेत्र देश का पांचवा सबसे बड़ा राज्य होगा रहेगा अभी भी पांच राज्यों की जनसँख्या मथुरा, रामपुर जिलों की जनसंख्या से कम है, छः राज्यों की जनसँख्या बिजनौर, बदायूँ ,मेरठ, अलीगढ, बुलंदशहर जिलों की जनसंख्या से भी कम है,सात राज्यों की जनसँख्या मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली, आगरा जिलों की जनसंख्या से कम है !पश्चिम क्षेत्र संसाधनों से भरपूर है जिस कारण यह कहना सही होगा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर यह राज्य भारत का सबसे विकसित राज्य होगा जहाँ हर जिले में डिग्री कॉलेज, हर मंडल में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर गाँव में इंटर कॉलेज होंगे, अपना हाई कोर्ट होगा,प्रदेश की राजधानी एंव सभी आयोग-मुख्यालय दो सौ किलोमीटर के दायरे में होंगे,सांस्कृतिक केंद्र होंगे, हर जिले में खेल संस्थान व स्टेडियम होंगे, बेहतरीन सड़कें-बस अड्डे होंगे, सस्ती यातायात सुविधाएँ होंगी नौकरियों के अवसर कई गुना बढ़ेंगे,किसानों और व्यापारियों की बेहतरी के लिए अधिक ध्यान दिया जायेगा।

जिलाधिकारी आगरा ने दो सबसे बड़े करदाताओं को किया सम्मानित, 500 करोड़ से अधिक का दिया टैक्स

मीडिया फॉर यू, आरिफ खान बाबा

आगरा। कलेक्ट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सबसे ज्यादा जीएसटी जमा करने वाले करदाताओं को सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने दोनों करदाताओं को सम्मानित किया। 500 करोड़ से अधिक का टैक्स जमा करने वाले पीएनसी इंफ्राटेक के मालिक पूर्व मेयर नवीन जैन के

भाई, राज्यसभा सदस्य भी हैं। वहीं एशियाई पेंट्स लिमिटेड ने 185.15 करोड़ का टैक्स वित्तीय वर्ष 2023 -24 में जमा कराया । जिलाधिकारी महोदय ने दोनों को सम्मानित किया।

हवाई अड्डे से गिरफ्तार- बुकी, 7:30 करोड़ का मामला

लुक आउट नोटिस था जारी। 16 सदस्य पहले से ही किये जा चुके हैं गिरफ्तार

मीडिया फॉर यू, आरिफ खान बाबा

आगरा। आगरा शहर में आए दिन फर्जी वाडा और धोखाधड़ी की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा शहर से जुड़े 7:30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। अवैध वायदा व्यापार से जुड़ै शहर की एक बुकी को हरियाणा के फरीदाबाद जिले की पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है वह देश छोड़कर भागने की तैयारी में था। फरीदाबाद पुलिस ठगों की तलाश में नेपाल तक गई थी। हालांकि पुलिस ने इस गिरोह के 16 सदस्यों को पहले ही पकड़ा जा चुका है पकड़े गए बुकी के खिलाफ पुलिस ने पहले से ही लुक आउट नोटिस जारी करा लिया था। सूत्र बताते हैं कि इन ठगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ में आया है जिसके तार चीन और नेपाल तक जुड़े हुए हैं। इस जांच में आगरा के बुकी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है जांच में बुकी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करा रखा था। सूत्रों के अनुसार एक महिला से 7:30 करोड रुपए ठगने वाले गिरोह के सदस्यों से इस बुकी के तार जुड़े हुए हैं। वित्तीय प्रबंधन पेशे से जुड़ी प्रियांशी गुप्ता निवासी फरीदाबाद से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7:30 करोड रुपए ठगे गए थे प्रियांशी ने मार्च में मुकदमा दर्ज कराया था इसके बाद से ही पुलिस ने आरोपियों की जांच कर धर पकड़ शुरू कर दी थी। जिसमें 16 सदस्य पहले से ही गिरफ्तार किये जा चुके थे बुकी के गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है वही अवैध वायदा व्यापार से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है सूत्रों की मानें तो बुकी के आगरा शहर के सत्ताधारियों और सराफा व्यापारियों के नजदीकी संबंध बताए जाते हैं।

मॉब लिंचिंग प्रकरण में सांसद इमरान मसूद मृतक के परिजनों से मिले, कांग्रेस की ओर से शोक संवेदना व्यक्ति की

मीडिया फॉर यू

गंगोह (सहारनपुर)। काजी शाहिद अहमद

मॉब लिंचिंग प्रकरण में कॉग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल लखनोती पहुंचा, और मृतक के परिवार जनों से मिलकर कांग्रेस की ओर से शोक संवेदना व्यक्ति की। बीते दिनों गंगोह ब्लॉक के ग्राम लखनौती के दो युवकों की छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के दौरान हुई हत्या के बाद रविवार को कॉग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिजनों से मिलने पहुँचा। तथा मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए कॉग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने हर संभव मदद दिलाने की बात कही। इस दौरान कॉग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सत्ता पक्ष बीजेपी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा की जनता से जो वादे भाजपा ने किए थे, वो सभी झूठे निकले। जिसका जवाब जनता ने लोकसभा चुनाव में

देकर साबित कर दिया की अब जनता जागरूक हो चुकी है। इस मौके पर सहारनपुर सांसद इमरान मसूद, पूर्व गंगोह चेयरमैन नौमान मसूद तथा युवा नेता हमजा मसूद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे।

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक परिवारों के साथ भेदभाव करने का आरोप

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता ने रविवार को भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मूल मूल्यों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक परिवारों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने कहा, 'भाजपा आरक्षण के मूल मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है। पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के परिवारों के साथ भेदभाव हो रहा है।' उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और यूपी से नियुक्त कुलपतियों में पीडीए के परिवारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीडीए के परिवारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यादव ने कहा, 'जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 15% से भी कम पीडीए परिवारों को नौकरी दी है। मौजूदा सरकार आरक्षण के पक्ष में नहीं है।'

1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह बनाए गए यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल समाप्त

>> मनोज कुमार मुख्य सचिव और आईडीसी दोनों होंगे
>> सीएम योगी के विश्वसनीय अफसर मनोज सिंह

मीडिया फॉर यू, आरिफ खान बाबा

लखनऊ। तेज तर्रार अफसरों में गिने जाने वाले 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कहा जा रहा था कि, दुर्गा शंकर मिश्रा को एक बार फिर से सेवा विस्तार मिल सकता है। हालांकि, चौथी बार उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला और मनोज कुमार सिंह प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए। आज दोपहर ही मनोज कुमार सिंह अपना कार्यभार संभालेंगे। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और ड़िक दोनों होंगे।

उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अधिकारी मनोज सिंह को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त होगा। अभी तक उनके पास पंचायती राज विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण सहित 6 से ज्यादा विभागों और संस्थाओं की जिम्मेदारी थी। वहीं ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश करार में मनोज सिंह की प्रमुख भूमिका रही है।

झारखंड की राजधानी रांची शहर में जन्मे मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश शासन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वह राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त और राज्य के औद्योगिक विकास आयुक्त भी रह चुके हैं। इसके अलावा पंचायतराज विभाग और हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव के रुप में सेवाएं दे चुके हैं।

मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड की राजधानी रांची शहर के निवासी हैं। वर्ष 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर हैं। वह गौतमबुद्ध नगर में पहली बार बतौर जिलाधिकारी 2 दिसंबर 1997 से 10 अप्रैल 1998 तक तैनात रहे। इसके बाद दूसरी तैनाती ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में हुई। तब 25 अप्रैल 2010 से 5 जुलाई 2010 छोटे कार्यकाल में काम किया था।

सीएम योगी के विश्वसनीय अफसर मनोज सिंह

मनोज सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे विश्वसनीय अफसर माना जाता है। इनके पास कई अहम विभागों की जिम्मेदारी रही हैं और शासन की कई योजनाओं को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका रही। इनकी नियुक्ति से सरकार को उम्मीद है कि प्रदेश में विकास कार्य और निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। मनोज कुमार सिंह की गिनती यूपी के प्रभावशाली नौकरशाहों में होती रही है।

अफसरशाही में मुख्य सचिव के बाद सबसे ताकतवर अफसर के रूप में सामने आए हैं। उन्हें जब पिछले महीने आईआईडीसी के पद पर तैनाती मिली तो चर्चा हुई कि लंबे समय बाद किसी अधिकारी को कृषि उत्पादन आयुक्त और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की जिम्मेदारी एक साथ दी गई है।

दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल समाप्त

दरअसल, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल रविवार को (आज) समाप्त हो रहा है। उन्हें दिसंबर 2021 में सेवानिवृत्ति से ठीक पहले सेवा विस्तार देकर उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। इसके बाद, उन्हें दिसंबर 2022 में और फिर दिसंबर 2023 में सेवा विस्तार मिला। हालांकि अब उन्हें चौथा सेवा विस्तार नहीं मिला और शासन ने आईएएस मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है।

हाजी वारिस अली की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

मीडिया फॉर यू

बाराबंकी: अशरफ अली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जनपद बाराबंकी दिनांक 29/06/2024 को देवा में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब बेग । जहां सर्वप्रथम पी डब्लू डी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की । पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि संगठन पूरे देश में जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु जागरूकता पर कार्य कर रहा है । पूरे देश से हाल ही में लगभग दो लाख लोग संगठन से जुड़े हैं। और

जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रयास किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा देश में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके । उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते जनता को योजनाओं से वंचित होना पड़ता है जोकि दुखद है ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी । इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे । और साथ ही बाकि कस्बा में अबरार उर्फ. मन्नू के निवास पहुंचकर अपने लोगों से मुलाकात की जहां पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया इस अवसर पर जिलाध्यक्ष निहाल अहमद सिद्धिकी, इरफान खान, मनोज जायसवाल, मतीन अब्दुल रशीद, अबरार उर्फ मन्नू, सहाबू, अकिल, तोहिद खान, फैसल,वैस खान आदि उपस्थित थे ।

01 JULY 2024 M4U:Layout 1 30-Jun-24 11:24 PM Page 4

संक्षिप्त समाचार

सीएमओ ने किया आयुष्मान भव मेले का निरीक्षण

मीडिया फॉर यू , देवीपाटन मंडल प्रभारी हाजी निसार उस्मानी

बलरामपुर : रविवार को जनपद बलरामपुर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैंसड़ी में आयोजित आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉ मुकेश कुमार रस्तोगी ने किया। आज जनपद में आयोजित आयुष्मान भव मेले में कुल 1343 लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया गया। सीएमओ ने निर्दिशित किया कि आयुष्मान भव मेले में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बरसात के मौसम में होने वाली संक्रामक बीमारियां जैसे डायरिया , मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया आदि से बचाव के संबंध में अवश्य जानकारी दें। निरीक्षण के समय डीपीएम शिवेंद्र मणि त्रिपाठी,अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैंसड़ी डॉ सुरेंद्र कुमार , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त चिकित्सक तथा कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

टाइगर राजा सिंह ने जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सहयोग करने के लिए किया आश्वासित: छाया गौतम

मीडिया फॉर यू, जितेंद्र शर्मा

जनपद मथुरा: वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन गोवा में टायगर राजा सिंह मथुरा से पहुँचे छाया गौतम एवं चंद्रकांत पांडेय को आश्वासन दिया कि भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई में ब्रजवासियों के साथ हूँ अब वो वक्त आ गया है अपने मन्दिरों को बचाने और हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हमें कट्टर हिंदुओं की अलग फौज बनानी होगी साहस और ऊर्जा के साथ बिना डरे बिना झुके हमें लड़ना होगा। अधिवेशन में आये सैकड़ों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के वकीलों ने एकजुटता के साथ कहा कि हम हिंदुत्व के कार्य में बिना किसी फीस के सभी हिन्दुवादियों की कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है करीब 400 हिन्दुवादी संगठनों के मुखियाओं ने एक साथ हुंकार भरी कि पूरी तैयारी और एकजुटता के साथ कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। अधिवेशन में आये सभी हिन्दुवादियों ने छाया गौतम एवं उनकी समस्त टीम के कार्यों एवं हिंदुत्व के लिए किए जा रहे संघर्ष की सराहना की और कहा कि हम सब हिंदू साथ साथ है।

धूमधाम के साथ मनाया गया जैन मिलन बड़ौत का 50 वां स्थापना दिवस

मीडिया फॉर यू, जितेंद्र शर्मा

जनपद मथुरा: जैन मिलन बड़ौत का 50 वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भारतीय जैन मिलन के क्षेत्र संख्या 5 की प्रथम क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। इसमें भारतीय जैन मिलन की बड़ौत, मेरठ, खेकड़ा, बागपत, हापुड़ की विभिन्न शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री एवं राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष वीर कमल जैन, चित्र अनावरणकर्ता वीर आदीश जैन एवं दीप प्रज्वलनकर्ता वीरांगना अंजली जैन रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय विशिष्ट संरक्षक वीर सुरेश जैन ऋतुराज, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर मनोज कुमार जैन ने अपने संबोधन मे कहा कि जैन समाज के ऊपर कभी भी कोई संकट आयेगा तो उसको बर्दाश्त नही किया जायेगा, उसका मुंहतोड जवाब दिया जायेगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदीप जैन एडवोकेट, क्षेत्रीय मंत्री वीरांगना राखी जैन, नवीन जैन बब्बल, शाखा अध्यक्ष वीर पुनीत जैन, शाखा मंत्री वीर अनुराग मोहन, डॉ संजय जैन (सन्मति हॉस्पिटल), डॉ संजय जैन (होम्यो), राजेन्द्र जैन कानूनगो, संजीव जैन डाबर, सुधीर जैन पत्थर वाले, सन्तोष जैन एडवोकेट, विकास जैन, मयंक जैन, आदिश जैन सबगे वाले, कमल जैन किताब, यश जैन पैट्रोल पम्प वाले सहित जैन मिलन परिवार के सभी पदाधिकारीगणों को सम्मानित किया गया।

प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगने का सिर्फ किया नाटक धर्म रक्षा संघ ने बैठक कर उठाया सवाल

मीडिया फॉर यू, जितेंद्र शर्मा

जनपद मथुरा: धर्म रक्षा संघ की एक बैठक भागवत मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्य आनंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें प्रदीप मिश्रा द्वारा बरसाना में आकर राधा रानी के समक्ष माफी मांगी गई के विषय में चर्चा हुई। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गॉड ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने बिना किसी पूर्व सूचना के चोरों की तरह बरसाना आकर माफी मांगने का मात्र नाटक किया है। धर्म रक्षा संघ इसकी इस माफी से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि 24 जून को हुई महापंचायत में तय हुई की माफी नामा की भाषा का पालन प्रदीप मिश्रा द्वारा नहीं किया गया धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक अचार बद्री महाराज ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने ब्रज में आकर संतों के प्रति किसी भी अपराध दिशा की भावना का प्रकृति कारण नहीं किया। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि बरसाना के संत पदम श्री रमेश बाबा महाराज एवं वृंदावन के रसिक संत प्रेमानंद महाराज के प्रति प्रदीप मिश्रा ने अपनी वाणी से एक शब्द भी नहीं बोला यह संत समाज का अपमान है महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की और फजियत ने हो इसके लिए हमें बोझिल मन से ही सही प्रदीप मिश्रा द्वारा किए गए अपराध को अब यहीं समाप्त कर देना है ।मगरधर्म रक्षा संघ की बैठक में प्रदीप मिश्रा के द्वारा माफी मांगने का सिर्फ नाटक बताया आलोचना करते हुए बताया

दहेज हत्या में पति और ससुर गिरफ्तार भेजा जेल

मीडिया फॉर यू, आरिफ खान बाबा

आगरा। थाना बासौनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव हजारपुरा में कुछ महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता मरणासन हालत में घर में पड़ी हुई मिली थी। जिससे हड़का मच गया था ।सूचना पर पहुंचे मायके के परिजनों ने जमकर हंगामा किया विवाहिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया ।जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था ।विवाहिता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति और ससुर को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। शनिवार को दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

प्राप्त सूत्रों के अनुसार, रवि परिहार पुत्र माता दिन निवासी माहिरा की थाना अंबा मध्य प्रदेश में पिछले महीने पुलिस को प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसने अपनी पुत्री किट्टू की शादी 23 जून को हिंदी रीति रिवाज से सचिन पुत्र पप्पू निवासी हजार पूरा थाना वसोनी के साथ धूमधाम से की थी और शादी में करीब 150लाख रुपए खर्च भी किए थे जिसमें पाच तोला सोना और दहेज का कीमती सामान देकर बेटी को विदा किया था। उसके बाद पति सचिन स सुमन ससुर पप्पू नंद अंजलि अभिलाख स्विफ्ट गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर बेटी को मानसिक आर्थिक रूप से उत्पत्ति करने लगे। 1 मई को सूचना पर पिता परिजनों के साथ बेटी के ससुराल हजारपूरा पहुंचा तो देखा उसकी पुत्री किट्टू मरणासन्न स्थिति में पड़ी मिली और मौके पर पति और ससुरालीजन कोई भी मौजूद नहीं मिला पिता पुत्री को लेकर आगरा पहुंचा और अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान पुत्री किट्टू की मौत हो गई।

जिला कारागार में योग का कार्यक्रम आयोजित योगासन प्राणायाम से स्वास्थ्य स्थिति सुधारें

मीडिया फॉर यू

बिजनौर: अतीक अहमद

चांदपुर बिजनौर में योगी अनंत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा ट्रस्ट साकेत कॉलोनी अध्यक्ष योगेश कुमार के निर्देशन में जिला कारागार में योग आसन और प्राणायाम कराया गया जिला कारागार में अधीक्षिका डॉक्टर अदिति जिला जेलर रविन्द्र नाथ जी जिला जेल प्रभारी अरविंद कुमार के द्वारा योग का कार्यक्रम आयोजित होता है आज योग गुरू डॉ नरेंद्र सिंह ने कैदीयों एवं समस्त स्टाफ को योगासन कराए जिसमें ग्रीवा संचालन स्कंद संचालन स्कंद खीचाव पादहस्तासन ताड़ासन पश्चिमोत्तानासन कटी चक्रासन भुजंगासन सलभासन धनुरासन शीर्षासन गोमुखासन वक्रासन अग्निसार क्रिया अनुलोम विलोम कपालभाति उज्जाई प्राणायाम रैकी क्रिया मूल बंधजालंधर बंध धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास कराया डॉ नरेंद्र सिंह ने कैदीयों से कहा यहां से अच्छे कर्म सीख कर जाए योगासन और प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें अपने परिवार को स्वस्थ रखें अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखने का संकल्प ले योग की ओर आने से स्थिति बदल जाएगी योग करने वालों को रोग होगा ही नहीं और होगा भी तो प्रकृति द्वारा ठीक कर दिया जाएगा प्रकृति स्वयं चिकित्सक है प्रकृति स्वयं हर जीव का इलाज करती है हमें स्वस्थ रहने के लिए योग आसन प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर वापस आना चाहिए जिससे हमारे समाज की हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और दवाईयों पर खर्च होने वाला धन राष्ट्र के विकास के कार्यों में लगेगा अतःराष्ट्र के निर्माण के लिए मानव के कल्याण के लिए पुनःयोग आसन और प्रकृति की ओर वापस आएं हैं योग गुरु सोमदत्त शर्मा ने कैदीयों को सूक्ष्म व्यायाम हास्य आसान कराया डॉक्टर गजेंद्र कुमार शर्मा ने बिना किसी दवाई के स्वस्थ रहने के उपाय बताएं और कहा कि बिना चिकित्सक की परामर्शदाता से के कोई दवाई ना खाएं कोई एंटीबायोटिक ना खाएं जहां तक हो सके दवाईयों से दूर ही रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह लें

रामदास अठावले ने हर्ष असरी को बनाया दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष

मीडिया फॉर यू, जितेंद्र शर्मा

जमपद मथुरा: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुप्रसिद्ध समाज सेवी हर्ष असरी को रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही आशा व्यक्त की कि हर्ष असरी के पार्टी का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बनने से पार्टी का संगठन और भी अधिक मजबूत होगा और पार्टी में एक नई जान आएगी। हर्ष असरी एक बहुत ही लोकप्रिय समाजसेवी है। यह बहुत लम्बे समय से केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के साथ जुडे हुए थे। केंद्रीय मंत्री की अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। वैसे तो यह पार्टी महाराष्ट्र में एक्टिव थी, पर अब इस पार्टी ने पूरे देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं। रामदास अठावले ने हर्ष असरी को अपनी पार्टी का दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया और नई जिम्मेदारियां दी। अपने दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बनने के बाद हर्ष असरी ने कहा कि पार्टी संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौपी है, उसका वह भली-भांति पालन करेंगे और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाकर संगठन को और भी अधिक मजबूत बनाया जाएगा। हर्ष असरी को दिल्ली का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें अनेक लोगों ने बधाई दी है।

डबल फाटक की सर्विस रोड निर्माण का कार्य शुरू

मीडिया फॉर यू

बिजनौर; अतीक अहमद

चांदपुर बिजनौर के नजीबाबाद फ्लाई ओवर ब्रिज की सर्विस रोड निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को भेजी एक शिकायत में अवगत कराया था कि नजीबाबाद में फ्लाई ओवर ब्रिज संख्या 483 डबल फाटक की मौजूदा सर्विस रोड जोकि गुरुद्वारे के पास से भारत गैस एजेंसी के कार्यालय पर समाप्त होती हैं उसमे दोनो तरफ जहां-तहां गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं इस कारण आने जाने वाले को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है तथा हर समय दुर्घटना का भय हर समय बना रहता है इसी संदर्भ में संबंधित मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय नजीबाबाद से रिपोर्ट मांगी गई थी जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व परियोजना निदेशक राजकुमार नागरवाल ने बताया था कि सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में अनुबंधित अथॉरिटी इंजीनियर को प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है आख्या प्राप्त होने उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाएगी इसी के तहत उक्त सर्विस रोड निर्माण के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है आरटीआई कार्यकर्ता ने उक्त सर्विस रोड निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सेतू निगम लोक निर्माण विभाग एनएचएआई को अलग अलग पत्र लिखकर अवगत कराया गया था

एसपी ने एक दरोगा व सिपाही को किया निलंबित

मीडिया फॉर यू

बिजनौर: अतीक अहमद

चांदपुर जिला बिजनौर में सोशल मीडिया पर 02 ऑडियो वायरल हुए है जिसमें 01ऑडियो में थाना कोतवाली देहात की चौकी चंडी देवी पर तैनात उ0नि0 विनोद कुमार पांडे व दूसरे ऑडियों में आरक्षी अमित कुमार द्वारा फोन कॉल पर वार्ता करते हुए दूसरे व्यक्ति से अनुचित लाभ की मांग की जा रही है उक्त दोनो वायरल ऑडियो का तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन जी ने जनपद बिजनौर द्वारा उ0नि0 विनोद पांडे व आरक्षी अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है इस सम्बंध में क्षेत्राधिकारी अपराध को जांच इस निर्देश के साथ दी गई है कि 03 दिवस में जांच पूर्ण कर आख्या प्रेषित करें आख्या प्राप्त होने के पश्चात विभागीय कार्यवाही भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगणों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे पुलिस जैसे अनुशासित विभाग की छवि धूमिल हो अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी दोनों के निलंबित होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है उधर सूत्रों का कहना है कि जब तक जनपद बिजनौर में ऐसे ईमानदार एसपी मौजूद हैं तो पुलिस विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों को इस तरह की मांगे खत्म करनी पड़ेगी

कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन एसडीम महोदय को सौपा

मीडिया फॉर यू

बिजनौर: अतीक अहमद

चांदपुर बिजनौर से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रांतीय आवाहन पर जनाब शाहनवाज आलम साहब के मुताबिक अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी बिजनौर के जिला अध्यक्ष वसीम अकरम एडवोकेट के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के चेयरमैन जनाब शाहनवाज आलम जी के निदेशानुसार पर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम छत्तीसगढ़ में सहारनपुर व शामली निवासी युवकों के साथ मोब लिंचिंग की घटना के विरोध में ज्ञापन दिया 7 जून 2024 को रायपुर-महासमुंद सीमा पर मोब लिंचिंग की घटना में यूपी के सहारनपुर निवासी सद्दाम कुरैशी 23 उसके चचेरे भाई गुड्डू खान 35 और चांद मिया खान 23 छत्तीसगढ़ के महासमुंद से रायपुर में मवेशी लेकर जा रहे थे इसी दौरान आरंग में महानदी नदी के पुल पर रोक लिया गया और उन पर भीड़ ने हमला किया पुलिस को तीनों पुल के नीचे पड़े मिले थे दो की उसी दिन मौत हो गई जबकि जीवित बचे एकमात्र चश्मदीद सद्दाम ने 18 जून को दम तोड़ दिया मोब लिंचिंग में अधिकतर गुंडे आजाद घूम रहे हैं इस तरह की लगातार हो रही घटनाएं देश की संवैधानिक व्यवस्था पर कलंक है ये छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में कानून व्यवस्था पर हमला है

राजनीतिक दलों के अभिकताओं के साथ बैठक संपन्न हुई

मीडिया फॉर यू

बिजनौर: अतीक अहमद

चांदपुर बिजनौर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए नियुक्त माननीय व्यय प्रेक्षक 04 लोकसभा क्षेत्र बिजनौर बसंत कुमार तथा 05 नगीना आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कपिल कुमार यादव की संयुक्तअध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के अभिकताओं के साथ बैठक संपन्न हुई इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह वरिष्ठ कोषाधिकारी विजय शंकर तिवारी सहायक व्यय पर्यवेक्षक तथा राजनीतिक दलों के व्यय से संबंधित अभिकर्ता एवं सदस्य मौजूद थे माननीय प्रेक्षक गणों ने राजनीतिक दलों से संबंधित अभिकताओं को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान खर्च के रूप में 90 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करना निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार आदि के दौरान हुए खर्चों से संबंधित अपना व्यय विवरण हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है उन्होंने निर्देश दिए की व आगामी 2 जुलाई 2024 तक अपने सभी व्यय से संबंधित अभिलेखों को कोषागार में जमा कर दें तथा निर्वाचन संबंधी जो खर्च हुआ है उनके बाऊचर हस्ताक्षर सहित होने चाहिए तथा व्यय रजिस्टर के प्रत्येक पेज पर भी हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि आगामी 4 जुलाई 2024 को निर्वाचन व्यय से संबंधित अंतिम रिपोर्ट आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी उससे पहले ही कोषागार में सहायक व्यय पर्यवेक्षक एवं व्यय लेखा टीम से संपर्क कर अपने व्यय से संबंधित बाऊचर्स का मिलान कर लें और उसके अनुसार व्यय पंजिका को भी दुरुस्त कर लें

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, नीरज कुमार गुप्ता ने मैं0 मोनेक्स ऑफसेट एस डी कांप्लैक्स निकट एमएमजी अस्पताल जी टी रोड, गाजियाबाद से मुद्रित कराकर बी 10/6 उमेश पार्क, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद से प्रकाशित किया। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र गाजियाबाद न्यायालय होगा। मोबाइल नं. 9870629696 संपादक नीरज कुमार गुप्ता